



झारखंड सरकार ने पेंशन योजना के लिये आयु घटाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, झारखंड कैबिनेट ने अपनी [वृद्धावस्था पेंशन योजना](#) में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं, [आदिवासियों](#) और दलितों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

- पहले 60 वर्ष से ऊपर वालों को योजना का लाभ मलित था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 1,000 रुपए प्रदान किये जाते हैं।

मुख्य बद्दि:

- यह पहल **मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना** के अंतर्गत आती है। इस नरिणय से करीब 18 लाख लोगों को लाभ होगा।
 - कुल 35.68 लाख लोगों को योजना का लाभ मलि चुका है।
- कैबिनेट ने गर्भवती महिलाओं को 'मातृ कटि' वतिरण समेत 25 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
 - लगभग 1,500 रुपए की कीमत वाली इस कटि में एक मच्छरदानी, एक सूती साडी, एक सूती तौलिया और एक टूथपेस्ट सहति 14 सामग्रियों होंगी। इससे 6 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
- कैबिनेट ने कई अन्य स्वीकृतियों भी दीं, जैसे:
 - राज्य पछिडा आयोग के अध्यक्ष पद पर योगेन्द्र प्रसाद की तीन वर्षों के लिये नयिकृति।
- गुमला ज़िले के वृंदा नायक टोली गाँव की रहने वाली वनीता ओराँव को रोज़गार और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार।
 - ओराँव ने 5 मई, 2020 को एक हमले के दौरान प्रतबिधति पीपुल्स लबिरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के एक एरिया कमांडर को मार डाला।
- 146 मध्य वदियालयों को उच्च वदियालयों में उत्कर्मति करना।

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के कमज़ोर बुजुर्ग नागरिकों को वतितीय सहायता प्रदान करना है।
- 1,000 रुपए मासिक पेंशन के प्रावधान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य वरषिठ नागरिकों को उनकी वतितीय आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर नरिभरता को कम करना है।
- यह योजना बुजुर्ग नागरिकों, वशिषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये आत्मनरिभरता पर ज़ोर देती है।

पीपुल्स लबिरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI)

- यह वर्ष 2007 में झारखंड में गठति एक उग्रवादी माओवादी संगठन है।
- पहले इसे झारखंड लबिरेशन टाइगर्स (JLT) के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में झारखंड के खूंटी ज़िले केनवासी दनिश गोप ने की थी।

झारखण्ड राज्य पछिडा आयोग

- यह एक स्थायी नकियाय है जिसका गठन झारखंड राज्य पछिडा वर्ग आयोग अधनियिम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार कया गया है।

